



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2008/कार्तिक 14, 1930

No. 389]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2008/KARTIKA 14, 1930

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

सं. 10(3)/2007-डी.बी.ए.-II/एन.ई.आर.-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के दिनांक 3 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007-डी.बी.ए.-II/एन.ई.आर. में मौजूदा पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

निम्नलिखित के स्थान पर :

1. 'प्रारंभ तथा अवधि' शीर्षक के तहत पैरा 2 में मौजूदा पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

"इस योजना को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के लिए 1 अप्रैल, 2007 से वर्तमान में लागू समान शर्तों और नियमों के अनुसार और आगे बढ़ाया जाता है। तथापि संभावित चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय करने के उद्देश्य से शीघ्र ही इस योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।"

यह पढ़ा जाए :

1. 'प्रारंभ तथा अवधि' शीर्षक के तहत पैरा 2 में मौजूदा पैरा के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

"इस योजना को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, केन्द्र शासित क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के लिए उन्हीं शर्तों और नियमों के अनुसार 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक बढ़ाया जाता है तथा इस बीच संभावित चोरी तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय करने के उद्देश्य से इस योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।"

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 5th November, 2008

No. 10(3)/2007-DBA-II/NER.—In the Department of Industrial Policy and Promotion's Notification No. 10(3)/2007-DBA.II/NER dated the 3rd April, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, the existing para will be read as follows :

Instead of :

1. In para 2, under the heading 'Commencement and Duration', the following may be added at the end of the existing para :—

"The Scheme is further extended from 1st April, 2007 for the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Darjeeling District of West Bengal, Union Territories of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, on the same terms and conditions as applicable at present. However, an early evaluation of the scheme will be carried out with a view to introducing necessary safeguards to prevent possible leakages and misuse."

Read as :

1. In para 2, under the heading 'Commencement and Duration', the following may be added at the end of the existing para :—

"The Scheme is further extended from 1-4-2007 to 31-3-2008 for the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Darjeeling District of West Bengal, Union Territories of Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep, on the same terms and conditions and in the meanwhile to carry out an evaluation of the Scheme with a view to introducing necessary safeguards in order to prevent possible leakages and misuse."

N. N. PRASAD, Jt. Secy.